केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) पहुंचे। अमित शाह ने सबसे पहले भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दूसरे रथ को रवाना किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह स्वयं परिवर्तन यात्रा रथ पर सवार हुये। इसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि, वर्तमान गहलोत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हुई है। इस मौके पर मंच पर पूर्व मु.मंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, राजेन्द्र राठौड़ सहित प्रदेश भाजपा के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि, भाजपा ने अपनी दूसरी परिवर्तन यात्रा वागड़ क्षेत्र में शुरु की है, गत शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भाजपा परिवर्तन यात्रा के पहले रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था।

'सनातन धर्म को खत्म करने की बात वोट बैंक और तुष्टिकरण के लिए कर रहा है विपक्ष'

अमित शाह ने बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दूसरे रथ को रवाना करते हुये कहा कि, ''इंडिया'' नहीं घमण्डिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है

- **अमित शाह ने कहा कि, भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा 19 दिन में करीब ढाई हजार किलोमीटर घूमेगी और 52 विधानसभाओं से संपर्क करेगी। इस दौरान 156 जगह छोटी सभाएं, 52 जगह पर सभाएं और 54 स्थानों पर बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लेने का काम करेगी।**

डूंगरपुर 3 सितंबर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन नैशनल डवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (आई.एन.डी.आई.ए.) पर देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण के लिए सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है।

शाह रविवार को डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम से भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' का शुभारंभ करने से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के लोग पिछले दो दिन से देश की संस्कृति, इतिहास और सनातन धर्म का अपमान कर रहे है। गठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके के बड़े नेता इनमें एक मुख्यमंत्री के पुत्र कह रहे है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर इसका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह चुके है कि बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है जबकि हम कहते है कि बजट पर पहला हक गरीबों, पिछड़ों आदि का है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से की जाती है और उनके मंत्री कहते थे कि हिंदू आतंकवाद चल रहा है।

शाह ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि यह गठबंधन वोट बैंक की राजनीति एवं तुष्टिकरण के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, लेकिन ये जितने इस तरह बोलेंगे उतने ही कम होते जायेंगे। उन्होंने कहा कि, अगर सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह राग अलाप किया तो आगामी 2024 में दूरबीन लेकर ढूंढेंगे तो भी नज़र नहीं आयेंगे।

अमित शाह ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के द्वितीय रथ को रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजित जनसभा को अमित शाह के अलावा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद कनकमल कटारा एवं अर्जुन मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने संबोधित किया।

शाह ने जनसभा में कहा कि, इस यात्रा की डूंगरपुर के इस क्षेत्र से शुरुआत होने जा रही है और यह देश भक्तों की भूमि रही है, जहां महाराणा प्रताप ने सालों युद्ध करते हुए मुगल सेना के दांत खट्टे करने का काम किया। उन्होंने कहा कि, भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा 19 दिन में करीब ढाई हजार किलोमीटर घूमेगी और 52 विधानसभाओं से संपर्क करेगी। इस दौरान 156 जगह छोटी सभाएं, 52 जगह पर सभाएं और 54 स्थानों पर बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लेने का काम करेगी।

इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि, केन्द्र में भाजपा की मजबूत सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत सबसे शक्तिशाली देश बनाने के मार्ग पर चल रहा है। चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच चुका है। उसी के साथ आदित्य एल-01 मिशन भी सफल तरीके से लांच हुआ है।

उन्होंने वर्ष 2013 के चुनाव में इसी क्षेत्र के सहयोग की वजह से भाजपा को एक ऐतिहासिक जनादेश मिला था। इस क्षेत्र में हमने मावजी महाराज और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली कालीबाई का पैनोरमा बनाने सहित कई काम किये है।

'एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघीय ढांचे की व्यवस्था एवं लोकतंत्र को ध्वस्त करने जैसा है'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, प्र.मंत्री मोदी का यह विचार उनकी तानाशाही सोच को दर्शाता है

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार का 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार संघीय ढांचे की व्यवस्था को ध्वस्त कर देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को तानाशाही व्यवस्था में तब्दील करना है।

खड़गे ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के विचार को लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बताया और कहा इस तरह का प्रयास करके मोदी सरकार देश के संघीय ढांचे को तानाशाही में तब्दील करना चाहती है।

राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और उसके इस विचार को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राज्यों पर हमला करार दिया। उनका कहना था कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से देश की संघीय प्रणाली के विरुद्ध है।

राहुल गांधी ने एक्स कर कहा, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार भारत संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। खड़गे ने कहा,मोदी सरकार का मकसद लोकतंत्र को धीरे-धीरे तानाशाही में बदलना है। उसका 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर समिति बनाना एक नौटंकी है और भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक बहाना है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत की प्रक्रिया बहुत जटिल है। निर्वाचित लोकसभा और विधान सभाओं के कार्यकाल को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की ज़रूरत है और इसके लिए संविधान में कम से कम पांच संशोधन कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा।

कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर सवाल करते हुए सरकार से पूछा,क्या प्रस्तावित समिति भारतीय चुनावी प्रक्रिया में सबसे बड़े बदलाव पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद मनमाने तरीके से की जानी चाहिए। क्या इतना बड़ा कदम राज्यों और उनकी चुनी हुई सरकारों को शामिल किए बिना उठाया जाना चाहिए।

खड़गे ने कहा कि इस तरह के विचार को पहले बनी तीन समितियों ने खारिज किया है और अब यह देखना है कि क्या इस मामले में चौथी समिति का गठन पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कमाल की बात यह है की जो समिति बनाई गई है उसमें चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है।

आजादी के बाद देश में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा,1967 तक हमारे पास न तो इतने राज्य थे और न ही हमारी पंचायतों में 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि थे।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनका भविष्य एक बार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब 2024 के लिए भारत के लोगों के पास केवल 'एक राष्ट्र, एक समाधान' का एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाना।

इससे पहले कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा,जिसे 'एक राष्ट्र एक चुनाव' कहा जा रहा है उस पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन एक अनुष्ठानिक अभ्यास है और इस काम की प्रक्रिया को सामने लाने का समय सन्देह पैदा करता है। इस संदर्भ में अपनाई गई शर्तें और सिफारिशें मनमानी से निर्धारित की गई हैं। समिति की संरचना भी अपने हिसाब से तय हुई हैं और इसी वजह से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल रात बहुत ही उचित तरीके से इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार किया है।

रमेश ने यह बात चौधरी की उस बयान के संदर्भ में कही जिसमें चौधरी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर गठित केंद्र की आठ सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए उसके इस कदम को देश के साथ धोखा बताया है।

उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को इस संदर्भ में शनिवार को लिखे अपने एक पत्र में कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एक धोखा है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा राज्य सभा जाएंगे

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के उप चुनाव में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है।

पार्टी की रविवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉ. दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश की राज्य सभा की एक रिक्त सीट के उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाने की स्वीकृति दी है। यह सीट राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से रिक्त हुई है।

इस सीट पर नामांकन के लिए 29 अगस्त को अधिसूचना जारी हो चुकी है। पांच सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आठ सितंबर है जबकि 15 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और उसी के बाद मतगणना होगी।

संसद सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, विधायी कामकाज ही निपटाये जायेंगे

- **संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है । हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है।**
- **मोदी सरकार के अब तक के नौ वर्षों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले हालांकि जीएसटी के लागू होने के अवसर पर जून 2017 की मध्यरात्रि को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलायी गयी थी।**

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा।वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने अपने बुलेटिन में कहा कि सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्यसभा का 261वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर तक चलेगा।

इसमें कहा गया है कि सत्र आमतौर पर पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा था कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है । हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधनी में जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है।

मोदी सरकार के अब तक के नौ वर्षों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले हालांकि जीएसटी के लागू होने के अवसर पर जून 2017 की मध्यरात्रि को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलायी गयी थी।

कर्नाटक में ऑपरेशन लॉटस फिर शुरु होगा

- **भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस ईश्वरप्पा ने दावा किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए राज्य में ऑपरेशन लोटस जल्द ही शुरू होगा।**
- **ईश्वरप्पा ने कहा, कांग्रेस के नेता राज्य में बड़ी-बड़ी न्यूज बनवा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के आधे विधायक हमारी पार्टी में आएंगे, लेकिन अभी तक तो एक भी भाजपा से कांग्रेस में नहीं गया है।**

बैंगलुरु, 3 सितम्बर। क्या कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू होने वाला है? भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा के बयान से ही यह सवाल खड़ा हुआ है। बीजेपी लीडर ने दावा किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए राज्य में ऑपरेशन लोटस जल्द ही शुरू होगा। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं रहने वाली है।

केएस ईश्वरप्पा शिवमोग्गा से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता राज्य में बड़ी-बड़ी न्यूज बनवा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के आधे विधायक हमारी पार्टी में आएंगे, लेकिन अभी तक तो एक भी भाजपा से कांग्रेस में नहीं गया है। ईश्वरप्पा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को भाजपा का कम से कम एक विधायक अपनी ओर लाने की चुनौती दी और इसके लिए एक महीने की समय सीमा भी तय कर दी। उन्होंने कहा, रुकिए और देखिए, कांग्रेस विधायकों को पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का इस देश में कोई भविष्य नहीं है।भाजपा नेता ईश्वरप्पा इससे पहले भी अपने बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में आए थे। इससे पहले जून में उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिदों को ढहाया जाएगा।

जिन सीटों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योजनाओं को लेकर लोगों को मोटिवेट करने का है। ये पर्यवेक्षक कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए लोगों से मिलने और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि, अब आगामी दिनों में पर्यवेक्षक विधानसभावार रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगामी दिनों में प्रदेश में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, यह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि, जिन सीटों पर पार्टी कमजोर हैं, उन सीटों पर पर्यवेक्षक खास ध्यान देंगे और पिछले चुनावों में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, ताकि ऐसी सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जा सके।

असम के मु.मंत्री ने कांग्रेस से डी.एम.के. के साथ गठबंधन भी तोड़ने की मांग की

मु.मंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने कहा कि, यह राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है। उन्हें इस बारे में निर्णय लेना होगा कि वह सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं

- **असम के सी.एम. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''मेरे पास उदयनिधि स्टालिन का बयान है और यही बयान कांग्रेस के एक सांसद चिदंबरम ने भी जारी किया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भी कमोबेश इसी तरह का बयान देखा है। उन्होंने कहा कि, इन नेताओं के बयानों से हिन्दुत्व विरोधी विचारधारा साफ झलक कर सामने आ रही है।**

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म किए जाने संबंधी दिए गए बयान पर सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विवादित टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने जमकर डीएमके और कांग्रेस पर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन में डीएमके के शामिल होने के चलते उदयनिधि के बयान की आंच अब कांग्रेस पार्टी तक आ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी को घेरा है। साथ ही, असम सीएम ने कांग्रेस से डीएमके के साथ गठबंधन भी तोड़ने की मांग की।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''मेरे पास उस नेता का बयान है और यही बयान कांग्रेस के एक सांसद चिदंबरम ने भी जारी किया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का भी कमोबेश इसी तरह का बयान देखा है। मेरे पास भी है।'' मैं तमिलनाडु के मंत्री की निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब भी डीएमके के साथ गठबंधन में रहेगी... यह राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है।

मोदी पुणे से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद पुणे लोकसभा सीट खाली होने के कारण, आगामी चुनावों में मोदी संभवत: इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे।

भाजपा के पूर्व सांसद संजय काकड़े ने सीधे मोदी को पत्र लिखकर उनसे पुणे से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा, जब आपने पिछला चुनाव गुजरात और उत्तर प्रदेश से लड़ा था, तो उन राज्यों में भाजपा को 90 से 100 फीसदी सफलता मिली थी. पुणे में आपकी जीत 100 फीसदी होगी।

अग्रवाल मारवाड़ी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एजुकेशन (एएमसीसीआईई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने भी मोदी के पुणे से चुनाव लड़ने की मीडिया रिपोर्टों का स्वागत करते हुए कहा कि पुणे को एक विश्व स्तरीय शहर और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रत्येक नागरिक का सपना सच हो जाएगा।

इतिहास में हुई मात्र तीन बैठकों में ही जी-20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुये थे

- **रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की अनुपस्थिति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में अनिश्चितता को लेकर जी 20 शिखर-सम्मेलन की कामयाबी को लेकर कुछ हलकों में कुछ टीका टिप्पणियां की जा रही हैं लेकिन तथ्य कुछ और ही कह रहे हैं कि, यह कोई नई बात नहीं है।**

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। आगामी जी20 शिखर सम्मेलन में कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति को लेकर भले ही कुछ अलग तरह की चर्चाएं चल रही हों लेकिन यह भी तथ्य है कि 2008 से अब तक हुए 16 शिखर-सम्मेलनों में से केवल शुरुआती तीन में ही सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था।

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की अनुपस्थिति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में अनिश्चितता को लेकर जी 20 शिखर-सम्मेलन की कामयाबी को लेकर कुछ हलकों में कुछ टीका टिप्पणियां की जा रही हैं लेकिन पिछले सम्मेलन पर निगाह डाली जाए तो कुछ और तथ्य सामने आते हैं।

पिछले रिकॉर्ड से पता चलता है कि वैश्विक शिखर सम्मेलनों में उपस्थिति का स्तर साल-दर-साल बदलता और व्यस्तताओं के चलते हर नेता के लिए हर शिखर सम्मेलन में भाग लेना हमेशा संभव नहीं होता है। कई बार नेता अपने निजी कारणों से शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले पाते हैं।

यहां सबसे उदाहरण इटली में वर्ष 2021 का जी20 शिखर सम्मेलन है जहां नेताओं के लिए इसे छोड़ने का कोई बड़ा भू-राजनीतिक या स्वास्थ्य कारण नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह से हुईं कि 20 सदस्य देशों में से छह देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की बजाय उनके प्रतिनिधि नेताओं ने भाग लिया था।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 से, जी 20 का प्रत्यक्ष रूप से 16 शिखर सम्मेलनों और एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन (सऊदी अरब, 2020) का आयोजन हो चुका है। वर्ष 2009 और 2010 में दो-दो शिखर सम्मेलन हुए। इन 16 प्रत्यक्ष शिखर सम्मेलनों में से, 2008 और 2009 के पहले तीन शिखर सम्मेलनों को छोड़कर, 2010 से अब तक एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब कि इसमें प्रत्येक देश ने राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तर पर भाग लिया हो।

जी 20 शिखर-सम्मेलन के इतिहास को देखें तो छह बार - 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 में एक देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष ने भाग नहीं लिया। पांच बार 2010, 2014, 2015, 2018, 2019 में दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष नहीं आये। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वर्ष 2022 में तीन देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल नहीं हुए।

वर्ष 2021 में (यूक्रेन युद्ध से पहले, कोविड के बाद) छह देशों के शीर्ष नेता नहीं आए थे।

ऐसे नौ देश - कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, दक्षिण कोरिया, तुर्क़, ब्रिटेन , अमेरिका , यूरोपीय संघ हैं जिन्होंने हमेशा हर शिखर-सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के स्तर पर शिरकत की है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने 2018 से स्वयं भाग नहीं लिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस ने दो बार तथा चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका ने एक बार राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष की बजाय किसी अन्य प्रतिनिधि नेता को भेजा है। सऊदी अरब ने नौ बार निचले स्तर के प्रतिनिधि के साथ शिरकत की जिसमें 2017 में एक बार बिना पोर्टफोलियो वाले राज्य मंत्री की भागीदारी शामिल है।

जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 इसी माह 9 और 10 तारीख को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला जी20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष ब्राजील में होगा।

सीट शेयरिंग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर में कट्टर प्रतिद्वंद्वी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद एक साथ आना मुश्किल हो सकता है।''

कांग्रेस पर अन्य दलों को समायोजित करने का भी दबाव है। बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों के दौरान लालू प्रसाद यादव, डी राजा और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस से उदारता दिखाने का आग्रह किया है। कई विपक्षी नेताओं के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेगी।

सोनिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होने के बाद यहां पहुंची तो उन्हें हल्का बुखार हुआ इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908